दिनांक
06-11-23

रैय्यतवाड़ी व्यवस्था :-

- अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तथा स्थायी बन्दोबस्त में अपेक्षाकृत लाभ न मिल पाने को ध्यान में रखते हुये रैय्यतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया।

- इस व्यवस्था में सरकार ने किसानों को भू-स्वामी मानते हुए राजस्व वसूली का दायित्व भी उन्हीं के साथ निर्धारित किया अर्थात सैद्धान्तिक रूप से यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी।

- यह ब्रिटिश भारत के लगभग- 51% भाग पर लागू की गयी जिसमें बम्बई मद्रास तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शामिल थे सर्वप्रथम कर्नल रीड ने इसे मद्रास के बारामहल क्षेत्र में (1792 में) अपनाया किन्तु इसे व्यवस्थित रूप 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा दिया गया।

अपनाने के कारण :-

- स्थाई बन्दोबस्त से अपेक्षाकृत लाभ ना मिल पाने के कारण एक लचीली व्यवस्था को अपनाना स्वभाविक हो गया जिसमें राजस्व की दर को परिवर्तित किया जा सके।
- अंग्रेजों ने रैय्यतवाड़ी को उन क्षेत्रों में अपनाया जहां की भौगोलिक तथा जलवायविक परिस्थितियां विशिष्ट थीं तथा वहां का सामाजिक- सांस्कृतिक ढांचा भी जमींदार जैसे किसी

मध्यस्थ वर्ग को अपनाने में सक्षम नहीं था अतः सरकार को यहां किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना आवश्यक था

- उपयोगितावादी विचारों से प्रेरित होकर अंग्रेज यह भी सिद्ध करना चाहते थे कि वे किसी भी अन्य शासन से अधिक लोकतांत्रिक हैं। अतः भारत में सुधार नीतियों के द्वारा वे भारतीयों की संवेदना भी हासिल करना चाहते थे।

इसके साथ ही उन्होंने "रिकार्डो के किराया सिद्धान्त" अर्थात "किसान के अधिशेष का हिस्सा सरकार को लेना न्याय संगत है" के आधार पर भी रैय्यतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया।

प्रावधान -:

- सैद्धान्तिक रूप से राजस्व की दर 50% निर्धारित की गयी तथा 20 से 30 वर्षों में राजस्व की दर को परिवर्तित करने का भी प्रावधान रखा गया।
- मापन व सर्वेक्षण के आधार पर राजस्व निर्धारित करने तथा कृषि व्यवस्था में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने की बात कही गयी।
- इस व्यवस्था की सफलता का दायित्व मुख्यतः कलेक्टर की भूमिका पर आधारित था और यह प्रावधान भी किया गया कि यदि कोई किसान नियत समय में लगान देने में असमर्थ है तो उसकी जमीन नीलाम कर दिये जाने का प्रावधान भी था।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

प्रभाव :-

- रैय्यतवाड़ी व्यवस्था की सफलता मुख्यतः कलेक्टर की भूमिका पर निर्भर थी किन्तु अधिक दायित्व होने और भारतीय कृषि पद्धति की जानकारी कम होने के कारण वह प्रभावी भूमिका नहीं निभा सका जिससे भ्रष्टाचार पनपने लगा और सरकारी कर्मचारियों ने किसानों से 80% तक की लगान वसूली की। इस तरह रैय्यतवाड़ी व्यवस्था सैद्धांतिक रूप में भले ही लोकतांत्रिक दिखती हो किन्तु यह किसानों के लिए शोषणकारी ही साबित हुई।

- मापन सर्वेक्षण व वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना केवल किताबों तक सीमित रहा और वास्तव में अधिकारियों की इच्छा व अनुमान के आधार पर ही राजस्व वसूली की जाती रही और जब किसान लगान देने में असमर्थ रहे तो उनकी जमीनें नीलाम होने से वे किसान से कृषक मजदूर बनने को विवश होने लगे।

- अंग्रेजो ने बड़ी चालाकी से अपनी भू-राजस्व नीतियों के द्वारा भारत की परंपरागत सामाजिक-आर्थिक संरचना को बदलते हुये जमीन को वस्तु बना दिया तथा भावना सहचर्यता की जगह बाजार प्रेरित व्यवस्था की नींव रखकर हमारे परंपरागत ढांचे को नष्ट कर दिया और नकदी फसलों की खेती तथा राजस्व वसूली नकद में किये जाने के कारण यहां के किसान ऋण

दुष्चक्र में फंसते गये इसीलिए किसानों ने शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हुये 1875 में प्रभावी दक्कन कृषक विद्रोह को अंजाम दिया।

प्रश्न- जमींदारी व्यवस्था से रैय्यतवाड़ी व्यवस्था में रूपान्तरण का अर्थ किसानों के दृष्टिकोण से मात्र इतना था कि अनेक राक्षसों की जगह एक महादैत्य ने ले ली।

महालवाड़ी व्यवस्था -:

- अंग्रेजों ने अपनी भू-राजस्व व्यवस्था के अन्तर्गत तीसरी व्यवस्था के रूप में महालवाड़ी को अपनाया जिसका उल्लेखनीय पक्ष यह था कि अब भूमि का स्वामित्व व राजस्व का दायित्व किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से स्थापित न कर सामुदायिक रूप से स्वीकारा गया तथा सरकार के पास राजस्व जमा करने का दायित्व लम्बरदार मुखिया को दिया गया। " यह जमींदार से इस रूप में अलग था कि इसके पास अधिक अधिकार या दायित्व नहीं थे।

- 1822 में हाल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को लागू किया और यह ब्रिटिश भारत के लगभग 30% क्षेत्र पर लागू किया गया जिसमें अवध, आगरा, पंजाब व पश्चिमोत्तर प्रांत शामिल थे।

- स्थायीतवाड़ी व्यवस्था की तरह ही इस व्यवस्था में भी मापन व सर्वेक्षण तथा वैज्ञानिकता को अपनाने की बात कही गयी किन्तु वास्तव में अनुमान के आधार पर ही राजस्व वसूली होती रही।

- 10 से 20 वर्षों में राजस्व की दर को परिवर्तित करने का प्रावधान रखा गया था किन्तु स्पष्टता की कमी के कारण किसानों से राजस्व वसूली 80% तक की जाती रही जिसे बेंटिंक व डलहौजी के कार्यकाल में क्रमशः 66% व 50% कर दिया गया। इस व्यवस्था की कमियों के कारण बाद में यह स्थिति उभरी कि प्रशासनिक खर्च अधिक होने लगा और राजस्व वसूली कम।

- लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में मार्टिन बर्ड द्वारा भू-राजस्व व्यवस्था में पहली बार मानचित्र व रजिस्टर का प्रयोग किया गया जो आज भी जारी है और इसीलिए बर्ड को उत्तर भारत की भू-राजस्व व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है।

इजारेदारी = ठेकेदारी / नीलामी

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

कृषि का वाणिज्यीकरण :-

- सामान्य शब्दों में कृषि उत्पाद को बाजारोन्मुख बनाना ही कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है।

इसके अन्तर्गत नकदी फसलों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो जाता है।

- वस्तुतः जब कृषि उत्पादन का लक्ष्य जीवन निर्वाह न होकर लाभ कमाना हो तो यही कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है।

- यद्यपि भारत नकदी फसलों से ऐतिहासिक रूप से परिचित रहा है किन्तु औपनिवेशिक शासन के दौरान यह विश्लेषण का विषय बन जाता है क्योंकि यह किसानों की इच्छा पर आधारित न होकर सरकार द्वारा थोपी गयी व्यवस्था थी।

सामान्यतः कृषि के वाणिज्यीकरण के लिये दो शर्तें अनिवार्य मानी जाती हैं-

(a)- देश/किसान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो।

(b)- कृषि विज्ञान से सम्बंधित महत्वपूर्ण अवसंरचनायें उपस्थित हों।

किन्तु उपरोक्त दोनों ही शर्तें औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुपस्थित थीं। और अंग्रेजों ने यूरोपीय एजेंसी हाउस के माध्यम से एक मध्यस्थ/एजेंट को बढ़ावा देकर भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण

कराया।

ये एजेंसी हाउस केवल अपने लाभ से प्रेरित थे और उन्हें किसानों के हितों से कोई सरोकार नहीं था। इन एजेंसी हाउस में अधिकांशतः भारत में बस जाने वाले अंग्रेज तथा कुछ ऐसे भारतीय शामिल थे जिन्होंने अंग्रेजों की सेवा कर कुछ पूंजी जमा कर ली थी।

कारण :-

- ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी अतः वहां के उद्योगों / कारखानों को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता थी। इस मांग से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भारत में नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया तथा समय व परिस्थितियों के अनुसार भारत में कपास, नील अफीम व गन्ना जैसी नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया।

भारत में नकदी फसलों की खेती के पीछे कुछ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी उत्तरदायी थीं उदाहरणतः नेपोलियन के युद्धों से जब वेस्ट इंडीज से नील आपूर्ति प्रभावित होने लगी अथवा अमेरिकी गृह युद्ध के कारण जब कपास की मांग पूरी ना हो सकी तो अंग्रेजों ने इनकी खेती के लिए भारत को विवश किया।

- ब्रिटिश विनिर्मित सामग्री के लिए भारत एक बेहतर बाजार तभी हो सकता था जब भारतीयों के पास क्रय क्षमता हो और बाजार में तरलता हो। अतः नकदी फसलों की खेती के द्वारा गांवों में भी नकद

प्रवाह को बढ़ाकर अंग्रेजों ने अपने उत्पादों की बिक्री का लक्ष्य रखा।

प्रभाव :-

- कृषि के वाणिज्यीकरण से अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत पक्ष अर्थात गांवों की आत्मनिर्भरता को तोड़ दिया। स्मरणीय है कि भारत के गांव आपसी सहचर्यता के आधार पर उत्पादन करते थे जिसे अंग्रेजों ने बाजार प्रेरित बनाकर प्रतिस्पर्द्धिता में बदल दिया। अर्थात अब किसान गांव के लिए नहीं बल्कि बाजार या ब्रिटिश हितों के लिए उत्पादन करने लगा इससे हमारी परंपरागत सामाजिक-आर्थिक संरचना ध्वस्त होने लगी।

- नकदी फसलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव तुलनात्मक रूप से अधिक होता है और खाद्य उत्पादन की तुलना में पूंजी भी अधिक लगती है अतः भारतीय किसानों पर शीघ्रतः इसका दुष्प्रभाव दिखने लगा क्योंकि लाभ तो यूरोपीय एजेंसी हाउस उठा लेते थे किन्तु हानि किसानों को ही सहनी पड़ती थी। इस सन्दर्भ में नील की खेती हमारे किसानों की दुर्दशा का विशेष उदाहरण बन गयी। और यह इतना शोषणकारी बन गयी कि 1860 में लोकप्रीय नील विद्रोह उभर पड़ा।

- नकदी फसलों व खाद्यान उत्पादन में असंतुलन तथा खाद्य सामग्री को भी अपने औद्योगिक मजदूरों के लिए भेजे

जाने के कारण भारत में अकाल और भुखमरी की स्थिति बढ़ती चली गयी और इसी सन्दर्भ में कहा गया कि "औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में पड़ने वाले अकाल प्राकृतिक कम व प्रायोजित अधिक थे।"

यद्यपि कृषि के वाणिज्यीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुये जैसे कि भारतीय कृषि का विविधीकरण हुआ और किसान नई फसलों से परिचित हुये तथा इन फसलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़क, रेल व बन्दरगाह जैसी अवसंरचनाओं का विकास किया गया जिससे न सिर्फ यातायात व परिवहन की गतिशीलता बढ़ी बल्कि भारत के बिखरे हुये क्षेत्र भी जुड़ने लगे और एकीकृत बाजार की संकल्पना सामने आयी।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

किन्तु कृषि के वाणिज्यीकरण के इन लाभों की तुलना में हमारे किसानों व गांवों पर नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ा और इस प्रचलन ने हमारे परंपरागत सामाजिक-आर्थिक ढांचे को नष्ट कर दिया। स्पष्टतः कहा जा सकता है कि " ब्रिटिश / औपनिवेशिक शासन का भारत पर प्रभाव का तत्वतः अर्थ था गांवों पर प्रभाव।

भारत
ग्रामीणकरण (2023)
की दर- 31%